(e) Government are not aware of any talks between Iran and Iraq for ending the Gulf war.

(f) Does not arise.

Licence to BEL for the manufacture of CTV Tubes

*92. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether M/s. Bharat Electronics Limited (BEL) has sought Government's approval to manufacture colour TV tubes;

(b) if so, whether it is a fact that some private sector firms manufacturing colour TV tubes have opposed the grant of licence to BEL to manufacture colour TV tubes;

(c) what are the details of the firms to whom Government have issued licences to manufacture colour TV tubes so far;

(d) what are the reasons for not permitting BEL to manufacture colour TV tubes so far; and

(e) by when Government propose to give its final approval to BEL?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Three firms have been granted approvals for foreign collaboration and import of capital goods by Government in the area of colour picture tubes as given below:—

(i) M/s Uptron Colour Picture Tubes Ltd., Sahibabad, U.P.

(ii) M/s Samtel Colour Ltd., Ghaziabad, U.P.

(iii) M/s. Punjab Display Devices Ltd. (now JCT Electronics Ltd.). Mohali, Punjab.

(d) and (e) BEL have so far only applied for a letter of intent for the manufacture of colour picture tubes, since they propose to locate the unit at their Jalahalli factory which falls within the standard urban area limit of Bangalore and hence requires a letter of intent. The company has yet to apply for foreign collaboration and import of capital goods.

संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में हिन्दी

***93. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 अक्तूबर, 1987 के अपने रात्रि बुलेटिन में आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) के दिल्ली स्टेशन से यह समाचार प्रसारित किया गया था कि मारीशस सहित यूरोप के अनेक देश हिन्दी को सयुक्त राष्ट्र की वैकल्पिक भाषा बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे है ; यदि हा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) यदि यह प्रस्ताव आता है तो क्या भारत पहल करेगा और इस संबंध में सहयोग देने की अपनी भूमिका निभायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) बताया जाता है कि लन्दन में आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन मे सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलवाई जाये । इसकी खबर आकाशवाणी से 28 अक्तूबर, 1987 को प्रसारित की गई थी । इस खबर के अनुसार इस सम्मेलन मे ब्रिट्रेन, भारत, हालैण्ड, जर्मनी, इटली और मारीशस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(ख) सरकार को अपनी स्थिति पर विचार करने में खुशी होगी यदि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किया जाता है ।